

आमदनी

न हुई दोगुनी

दर्द

सौ गुना





आइए सिलसिलेवार जानते हैं:-

1. किसानों की बदहाली की कहानी मोदी सरकार की रिपोर्ट की जुबानी

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSSO) द्वारा ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों की स्थिति को लेकर सितंबर, 2021 में रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत के किसानों की जो दुर्दशा सामने आई है, उसे शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन है। भाजपा व प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करते रहते हैं। इस रिपोर्ट को पढ़कर पता चलता है कि पूंजीपतियों को पूजने वाली मोदी सरकार ने आय दोगुनी करने की अपेक्षा खेती की लागत को कई गुना बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, भारत के किसानों को मोदी सरकार ने आकंट कर्ज में भी डुबो दिया।

लागत में लगी आग, आमदनी हुई खाक

किसान परिवारों का फसल उत्पादन पर औसतन मासिक व्यय ₹2,959 है, जिसमें औसतन बीज का 341 रु., खाद का 615 रु., कीटनाशक का 246 रु., सिंचाई का 120 रु., रिपेयर मेंटेनेंस का 138 रु., ब्याज का 48 रु., जमीन का लीज रेंट 200 रु., मजदूरी की लागत 654 रु. और जानवर पर खर्च 37 रु., अन्य खर्च 661 रु., अर्थात् कुल - 2,959 रु. और किसान को फसल उत्पादन से प्रति माह प्राप्ति ₹6,960 होती है (जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच)। अर्थात् पाँच व्यक्तियों के एक परिवार में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मात्र ₹ 26.67 ही खेती से कमा रहा है।

कर्ज में आकंट डूबा किसान

आमदनी बढ़ाने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने किसान को आकंट कर्ज में डुबा दिया है। भारत के 50.2 प्रतिशत किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनका प्रति परिवार औसतन ऋण 74,121 रु. है। कई राज्यों में तो यह स्थिति भयावह है। आंध्र प्रदेश में औसत प्रति किसान पर 2,45,554 रु. का कर्ज है, केरला में 2,42,482 रु., हरियाणा में 1,82,922 रु., कर्नाटक में 1,26,240 रु. का कर्ज है।

खेती से हुए दूर, किसान हैं मजदूरी को मजबूर

इस रिपोर्ट में इस बात का चौंकानेवाला खुलासा हुआ है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान परिवार खेती की अपेक्षा मजदूरी करने को अधिक मजबूर हैं। किसानों को होने वाली आमदनी में 39.8 प्रतिशत हिस्सा वो प्रतिमाह मजदूरी से अर्जित कर रहे हैं जो कि औसतन 4,063 रु. प्रतिमाह है और फसल उत्पादन से 37.2 प्रतिशत जो कि औसतन 3,798 रु. प्रतिमाह है।

पशुपालन भी नहीं फायदे का सौदा

पशुपालन में लगे किसान-मजदूर परिवारों का पशुपालन पर औसतन मासिक खर्चा 1,267 रु. प्रति माह आता है, जिसमें पशुओं के खाने की व्यवस्था (फीड एंड सीड), वेटेरिनरी सर्विस - ₹70, लेबर चार्ज - ₹32, अन्य खर्च - ₹38, कुल खर्च - ₹1,267। और उसे इस एवज में मासिक आमदनी मात्र ₹3,704 होती है। अर्थात् किसान मात्र ₹16.24 प्रतिदिन ही कमा पाता है।

भारत के लोग सब पर विश्वास करते हैं मगर जो विश्वासघात करे उसे कभी माफ नहीं करते। मोदी सरकार व भाजपा ने भारत के भाग्यविधाता अन्नदाता किसानों पर जो आघात किया है, उनसे जो विश्वासघात किया है, उसे भारत कभी माफ नहीं करेगा।

श्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी, 2016 को बरेली, उत्तर प्रदेश की रैली में देश के किसानों से वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय तो दोगुनी हुई नहीं, दर्द सौ गुना जरूर हो गया।

छ: साल बाद मोदी सरकार ने सितंबर, 2021 में NSSO की रिपोर्ट जारी कर बताया कि किसानों की औसत आय ₹27 प्रतिदिन रह गई है और औसत कर्ज ₹74,000 प्रति किसान हो गया है। इसका मूल कारण यह है कि मोदी सरकार ने न पर्याप्त समर्थन मूल्य बढ़ाया, न ही समर्थन मूल्य पर खरीदी की।

पूत के पाँव पालने में:

मोदी सरकार व भाजपा का DNA ही किसान-मजदूर विरोधी है -

- मई, 2014 में सत्ता में आते ही भाजपा व मोदी सरकार किसानों की जमीन हड़पने के लिए, उनके जमीन के उचित मुआवजा कानून के खिलाफ एक के बाद एक तीन अध्यादेश लेकर आई।
- फिर गेहूँ एवं धान पर राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला ₹150 का बोनस बंद करा दिया।
- फिर सुप्रीमकोर्ट में शपथपत्र देकर कह दिया कि लागत का 50 प्रतिशत ऊपर समर्थन मूल्य दिया तो बाजार बर्बाद हो जाएगा।
- फिर निजी कंपनियों के मुनाफे की फसल बीमा योजना लागू की गई।
- फिर टैक्स पर टैक्स लगा खेती की लागत ₹25,000 प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी।
- फिर अपने मुट्ठीभर पूंजीपति दोस्तों के लिए खेती विरोधी तीन काले कानून लाए। इतना ही नहीं, 700 किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। उनके सिर फोड़ने के आदेश देकर लहू-लुहान किया गया। उनके रास्ते में कील-काँटे बिछाए गए। इससे भी पेट नहीं भरा तो उन्हें लखीमपुर-खीरी में जीप से सौंदकर मार डाला गया।

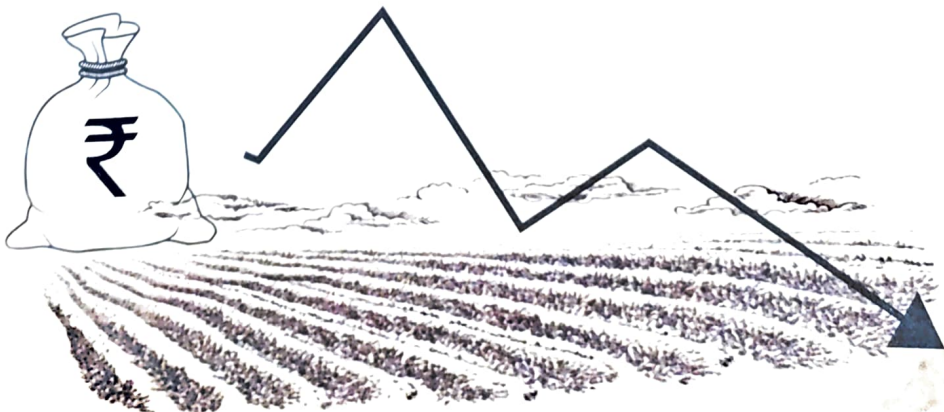
समर्थन मूल्य का सच

मोदी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में खुद इस बात का खुलासा किया है कि धान और गेहूँ को छोड़कर कोई भी फसल MSP पर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं खरीदी जाती। इतना ही नहीं, खुले बाजार में अच्छे दाम मिलने का दावा करने वाली मोदी सरकार की पोल खुल गई। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2019 के बीच 0 से 0.5 प्रतिशत ही फसलों को समर्थन मूल्य से अधिक कीमत बाजार में मिली है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बाजार मूल्य तो MSP से भी कम था और 57.4 प्रतिशत किसानों को उस बाजार मूल्य (जो MSP से कम था) से भी कम दाम मिले हैं।

January 2018-December 2018			
Percentage of Households Among those Reporting sale of Crops			
Crop	Sold to Procurement Agency	Received Better Price Over MSP	Lower than Below-MSP Market Price
Paddy	14.5	0.5	37.1
Jowar	3.5	0.0	27.5
Bajra	2.1	0.0	35.0
Maize	4.1	0.2	34.6
Ragi	0.0	0.0	37.7
Arhar(Tur)	3.0	0.0	41.3
Urad	5.4	0.0	57.4
Moong	2.5	0.0	38.3
Sugarcane	27.9	0.3	22.7
Groundnut	5.6	0.0	40.7
Coconut	1.0	0.0	28.2
Soyabean	8.6	0.0	39.8
Cotton	8.0	0.1	32.4

January 2019-December 2019

Paddy	18.5	0.5	32.3
Jowar	0.7	0.0	26.6
Maize	6.0	0.4	27.3
Wheat	9.7	0.2	30.5
Gram	5.4	0.0	31.9
Arhar(Tur)	1.4	0.0	32.2
Moong	5.5	0.0	34.1
Masur	1.8	0.0	38.9
Sugarcane	40.7	0.0	14.0
Rapeseed /Mustard	5.1	0.0	37.5
Coconut	0.3	0.0	25.9
Cotton	12.8	0.0	38.2



2. समर्थन मूल्य पर मुट्ठीगर खरीद का सच आया सामने

भाजपा व मोदी सरकार पर्याप्त मात्रा में समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज नहीं खरीद रही। मोदी सरकार ने 14 दिसंबर, 2021 को लोकसभा में बताया कि यदि धान और गेहूँ को छोड़ दिया जाए तो मात्र 0.26% से लेकर 8.64% तक ही अनाज MSP पर खरीदा जा रहा है। निम्नलिखित चार्ट सच्चाई उजागर करता है कि कितनी कम मात्रा में भाजपा सरकार किसानों से अनाज MSP पर खरीदती है :-

Crop	2020-21			
	Production (MT)	Procurement (MT)	Number of Farmers Benefitted	Percentage of Procurement
Gram	1,19,90,000	6,36,906	4,02,694	5.31
Masoor	8,00,000	18	1,89	0.002
Moong	30,90,000	2,67,391	14,422	8.65
Toor	42,80,000	11,004	769	0.26
Urad	20,10,000	1,087	173	0.05
Groundnut	1,02,10,000	2,86,233	1,52,426	2.8
Sunflower seed	2,30,000	3,886	3,101	1.69
Jowar	47,80,000	1,46,472	38,090	3.06
Bajra	1,08,60,000	3,61,871	44,166	3.33
Maize	3,15,10,000	2,05,315	54,012	0.65



3. 'स्वामीनाथन' बनाम 'मोदीनाथन' का सच:

मोदी सरकार ने 9 फरवरी, 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि किसानों को लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा नहीं दिया जा सकता। हाल ही में 2022-23 के रबी फसलों और 2021-22 की खरीफ फसलों के MSP की घोषणा भी धोखे की इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आइये जानते हैं कि वर्तमान में रबी और खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया गया और कृषि लागत व मूल्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर किसानों को "लागत+ 50 प्रतिशत मुनाफा" दिया जाता, तो किसानों को कितना समर्थन मूल्य मिलता।

रबी मार्केटिंग सीज़न 2022-23 (Rs./quintal)

Crops	Cost of Production CACP (C2)	MSP for RMS 2022-23 (Modi-Nathan)	MSP = Cost+50% (Swaminathan)
गेहूँ (Wheat)	₹ 1,518	₹ 2,015	₹ 2,277
जौ (Barley)	₹ 1,439	₹ 1,635	₹ 2,158
चना (Gram)	₹ 4,117	₹ 5,230	₹ 6,175
अरहर (Lentil)	₹ 4,422	₹ 5,500	₹ 6,633
कैनोला और सरसों (Rapeseed & Mustard)	₹ 3,506	₹ 5,050	₹ 5,259
सूरजमुखी (Sunflower)	₹ 5,050	₹ 5,441	₹ 7,575

4. किसान सम्मान निधि में 6,000 रु. दिए, लागत बढ़ाकर 25,000 रु. लूट लिए

मोदी सरकार ने 1 दिसंबर, 2018 से किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की थी, जिसके तहत दो-दो हजार रु. की तीन किश्तों में 6,000 रु. प्रत्येक किसान के खाते में डालने की बात कही गई थी। इस योजना के तहत 11.61 करोड़ किसानों के खाते में यह पैसा हस्तांतरित किया जा रहा है। जबकि एग्रीकल्चर सेसस के अनुसार भारत में 14.65 करोड़ किसान हैं। अर्थात् अभी भी लगभग 3.04 करोड़ किसानों के खाते में यह राशि हस्तांतरित नहीं की जा रही।

मोदी सरकार ने एक तरफ सालाना 6,000 रु. प्रति किसान रवांग किया, तो दूसरी तरफ सालाना 25,000 रु. प्रति हैक्टेयर जेब काटकर छीन लिए :-

- डीजल पर केंद्रीय एक्साईज ड्यूटी साल, 2014 में ₹3.56 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹31.80 प्रति लीटर कर दी। हाल में ही उपचुनाव हारने के बाद ₹10 प्रति लीटर कम तो किए गए पर आज भी डीजल पर एक्साईज ड्यूटी ₹21.80 प्रति लीटर है। यानि 2014 के मुकाबले में हर लीटर डीजल पर मोदी सरकार ₹18.24 प्रति लीटर अतिरिक्त टैक्स वसूल रही है। अकेले पेट्रोल-डीजल पर एक्साईज लगाकर मोदी सरकार ने सात सालों में 24 लाख करोड़ रु. कमाए हैं।

- पहली बार खेती पर टैक्स यानि जीएसटी लगाया गया। ट्रैक्टर व खेती के उपकरणों पर 12 प्रतिशत टैक्स। ट्रैक्टर के टायर व अन्य पुर्जों पर 18 प्रतिशत टैक्स। खाद पर 5 प्रतिशत टैक्स। कीटनाशक दवाइयों पर 18 प्रतिशत टैक्स।

- खाद की कीमतों में अनाप-शनाप बढ़ोत्तरी की गई। DAP खाद के 50 किलो के बैग की कीमत रातोंरात ₹1200 से बढ़ाकर ₹1900 कर दी गई। चौतरफा विरोध के बाद भाजपा ने बढ़ी कीमत तो वापस ले ली, पर DAP खाद मिला ही नहीं। और किसान को मजबूरन ब्लैक मार्केट में ₹2200 प्रति बैग तक खरीदना पड़ा।

भाजपा सरकार ने यूरिया खाद के 50 किलो के कट्टे से 5 किलो खाद ही चोरी कर लिया। यूरिया खाद का कट्टा तो 45 किलो का हो गया, पर कीमत वही रही। ऊपर से पहले किसान DAP खाद के लिए पिटा और अब यूरिया खाद की कमी में लुटा।

पोटाश खाद के 50 किलो के बैग की कीमत साल, 2014 में ₹450 से बढ़ाकर ₹825 कर दी गई है। सुपर खाद के 50 किलो के बैग की कीमत भी साल, 2014 के ₹260 से बढ़कर ₹340 हो गई है।

- बीज और बिजली की कीमतों में भी इसी प्रकार से बढ़ोत्तरी की गई।

मोटे तौर पर मूल्यांकन किया जाए, तो मोदी सरकार ने प्रति वर्ष किसानों से 25,000 रु. हैक्टेयर खेती की लागत बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रु. साल एंटना शुरू कर दिया, यानि 7 सालों में 17.50 लाख करोड़। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर 1 दिसंबर, 2018 से आज तक मात्र 1,61 लाख करोड़ रु. ही किसानों को दिए। यानि लगभग 15 लाख करोड़ रु. किसान की जेब से निकाल लिए।

5. समर्थन मूल्य : कांग्रेस बनाम मोदी सरकार

कांग्रेस सरकार ने 2006-07 से 2013-14 के बीच समर्थन मूल्य में 205 प्रतिशत तक की वृद्धि की थी। वहीं मोदी सरकार ने धान में मात्र 48 प्रतिशत और गेहूँ में मात्र 43 प्रतिशत की वृद्धि की।

Crop	2006-2007	2013-2014	Change	2021-22	Change
Paddy (Common)	₹ 580	₹ 1,310	126%	₹ 1,940	48%
Wheat	₹ 750	₹ 1,400	87%	₹ 2,015	43.92%
Gram	₹ 1,445	₹ 3,100	115%	₹ 5,203	68%
Tur (Arhar)	₹ 1,410	₹ 4,300	205%	₹ 6,300	46%
Maize	₹ 540	₹ 1,310	143%	₹ 1,870	42%
Masoor	₹ 1,545	₹ 2,950	90%	₹ 5,500	86%

(Rate Rs. Per quintal)

किसान को मोदी-नाथन नहीं, मेहनत की कीमत चाहिए। अगर मोदी सरकार ने अन्नदाता से षडयंत्र बंद नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां भाजपा को माफ नहीं करेंगी।

6. निजी बीमा कंपनियों की "किसान लूट योजना"

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे फरवरी 2016 में मोदी जी ने यह कह कर लागू किया था कि यह विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना है, इस योजना का हाल यह है कि प्रधानमंत्री के अपने प्रांत, गुजरात ने इस पर ताला लगा दिया है।

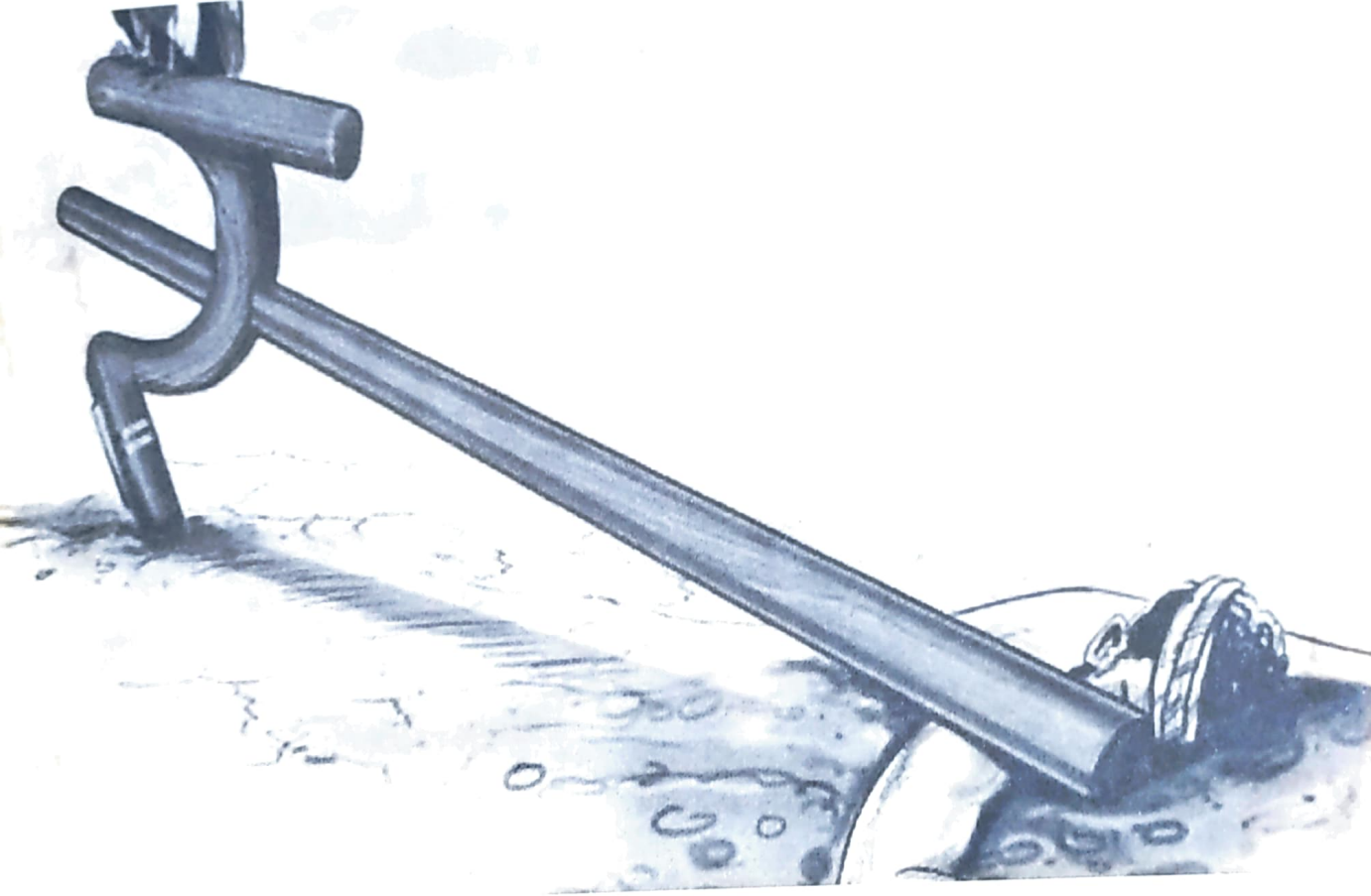
जब से यह योजना लागू की गई है देश के किसानों से प्रीमियम के नाम पर 21,450 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि निजी कंपनियों ने साल 2016 से 2020-21 तक 30,320 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया है।

Company	Profit (In Rs. Crore)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
AIC	2412.3	--	601.9	787.6	11854.6
Bajaj Allianz	363.4	623.1	360	605.5	1988.9
Chola MS	108.6	--	--	--	--
Future Generali	110.9	--	195.6	590.4	734.1
HDFC Ergo	538.5	466.7	422.1	1200.8	1432.3
ICICI Lombard	252.4	--	341.3	--	--
IFFCO Tokio	681.8	--	658.4	571.7	2246.6
National	165.5	--	218.6	--	--
New India	--	976.6	--	--	--
Oriental	4.2	--	--	--	--
Reliance General	739.2	583.1	479.2	1044.4	1886
SBI General	312	467.9	48.2	17.1	610
Shriram General	--	--	--	--	--
Tata AIG	--	--	303.1	--	--
United India	470.4	460.6	--	20.9	--
Universal Sompo	--	1112.3	482.1	1135.2	771.8
Bharti AXA	--	270.4	196.3	760.4	638.1
Royal Sundaram	--	1.6	139.2	590.2	--



7. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बना एक जुमला

मोदी सरकार ने बड़े जोर-शोर से यह प्रचारित किया था कि हम हिंदुस्तान में किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में कदम आम बड़ा रहे हैं और एक लाख करोड़ रु. का एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जा रहा है। दिसंबर 2021 तक इसमें से मात्र 6098 करोड़ रु. का लोन स्वीकृत किया गया है, जिसमें से मात्र 2071 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। जिससे समूचे देश में मात्र 685 किसान, 61 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और 2,576 कृषि क्षेत्र में व्यापार करने वाले लोग ही इस स्कीम में शामिल हो पाए। शर्मनाक बात है कि किसानों के साथ यह कुठाराघात किया जा रहा है।



8. अन्नदाता को आत्महत्या का अभिशाप

दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा व मोदी सरकार की किसान-खेत मजदूर नीतियों के चलते साल 2014 से 2020 के बीच 78,303 किसान-खेत मजदूर आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर हो गए। तमिलनाडु के किसान अपने साथी किसानों के नरककाल और खोपड़ी लेकर जंतर-मंतर से प्रधानमंत्री निवास तक गुहार लगाते रहे पर मोदी जी ने एक न सुनी।

भाजपा व मोदी सरकार का झूठ साफ है। 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा तो की, मगर वर्ष-दर-वर्ष किसानों के साथ कुठाराघात किया गया और किसानों की आय दोगुना करने की अपेक्षा दस गुना कम कर दी।

भाजपा के किसान-विरोधी चेहरे का इससे बड़ा सबूत क्या है कि 380 दिन से अधिक लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर न्याय मांगते रहे, 700 किसानों ने कुर्बानी दी पर प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलना तक उचित नहीं समझा। उपचुनाव की हार के चलते तीनों खेती विरोधी काले कानून वापस तो लिए, पर अब चोर दरवाजे से उन्हें लाने की फिर तैयारी है।

पाँच राज्यों के चुनाव में वोट की चोट ही किसान-विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को सच्चाई का आईना दिखाएगी। भाजपा की हार में ही किसान-खेत मजदूर की जीत है।

अन्नदाता का अवसर आया है

दिल्ली के दरबारों ने,
सत्ता के गलियारों ने,
अहंकारी सरकारों ने,
दमन चक्र चलाया है,
धरती के भगवान को,
खेत मजदूर—किसान को,
सत्ता ने बहुत सताया है,
कील और नशतर का बिस्तर बिछवाया है,
लहुलुहान किया है उनको,
खून बहुत बहाया है।

दोगुना आमदनी का झाँसा देकर
वोट फक्त हथियाया है।

सत्ता का घमंड तोड़ने,
हवाओं का रुख मोड़ने,
अन्नदाता अब आया है।

कल तक तुम्हारी बारी थी,
अब उसका अवसर आया है।

